संपादकीय

शरीफः प्रधानमंत्री या प्रधानभिक्षु?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आजकल प्रधानमंत्री कम, प्रधानभिक्षु बनकर देश-विदेश के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्हें सउदी अरब जाकर अपना भिक्षा-पात्र फैलाना पड़ा। तीन-चार दिन पहले वे अबू धाबी और दुबई आए हुए थे। संयोग की बात है कि दो-तीन दिन के लिए मैं भी दुबई और अबू धाबी में हूं। यहां के कई अरबी नेताओं से मेरी बात हुई। पाकिस्तान की दुर्दशा से वे बहुत दुखी हैं लेकिन वे पाकिस्तान पर कर्ज लादने के अलावा क्या कर सकते हैं?

उन्होंने 2 बिलियन डॉलर जो पहले दे रखे थे, उनके भुगतान की तिथि आगे बढ़ा दी है और संकट से लड़ने के लिए 1 बिलियन डॉलर और दे दिए हैं। शहबाज की झोली को पिछले हफ्ते भरने में सउदी अरब ने भी काफी उदारता दिखाई थी। लेकिन पाकिस्तान की झोली में इतने बड़े-बड़े छेद हैं कि ये पश्चिम एशियाई राष्ट्र तो क्या, उसे चीन और अमेरिका भी नहीं भर सकते। इन छेदों का कारण क्या है? इनका असली कारण है- भारत। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की फौज और सरकार ने इतनी नफरत कूट-कूटकर भर दी है कि उस राष्ट्र का ध्यान खुद को संभालने पर बहुत कम लग पाता है। इसी नफरत के दम पर पाकिस्तान के नेता चुनावों में अपनी गोटी गरम करते हैं। वे कश्मीर का राग अलापते रहते हैं और फौज को अपने सिर पर चढ़ाए रखते हैं। आम जनता रोटियों को तरसती रहती है लेकिन उसे भी नफरत के गुलाब जामुन कश्मीर की तश्तरी में रखकर पेश कर दिए जाते हैं। पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात गए। वहां भी उन्होंने कश्मीर का राग अलापा। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की पहल की, जो कि अच्छी बात है लेकिन साथ में ही यह धमकी भी दे डाली कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया तो कोई नहीं बचेगा। दोनों के पास परमाणु बम हैं। शहबाज ने अबू धाबी के शासक से कहा कि भारत से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप मध्यस्थता क्यों नहीं करते? एक तरफ वे मध्यस्थता की बात करते हैं और दूसरी तरफ, वे भारत से कहते हैं कि आप संयुक्तराष्ट्र संघ के प्रस्ताव के मुताबिक कश्मीर हमारे हवाले कर दो। पाकिस्तान के दो-तीन प्रधानमंत्रियों से मेरी बहुत ही मैत्रीपूर्ण बातचीत में मुझे पता चला कि उन्होंने संयुक्तराष्ट्र के उस प्रस्ताव का मूलपाठ कभी पढ़ा ही नहीं है। उन्हें यह पता ही नहीं है कि उस प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान पहले तथाकथित 'आजाद कश्मीर' को खाली करे। शहबाज को चाहिए था कि वे आतंकवाद के विरुद्ध भी कुछ बोलें। लेकिन ऐसा लगता है कि अबू धाबी में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह यहां के शासकों को खुश करने के लिए कहा है। यह शहबाज शरीफ की ही नहीं, पाकिस्तान के सभी नेताओं की मजबूरी है कि जो लोग उनकी झोली में कुछ जूठन डाल देते हैं, उन्हें कुछ न कुछ महत्व तो देना ही पड़ता है। आखिर में खाली भिक्षा-पात्र को भरा जाना ही है, हर शर्त पर! इसीलिए दोनों नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में शहबाज के उक्त बयान का जिक्र तक नहीं है।

चीन की 'आतंकी' चाल, पाकिस्तान का 'मक्की' जैसा हाल

दृष्टिकोण

-विक्रम उपाध्याय

पाकिस्तान लगभग तीन महीने पहले ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। मगर उसकी आतंकपरस्त आदत उसके लिए भारी पड़ गई है। 16 जनवरी,2023 को यूएनओ के कुख्यात अब्दुल रहमान मक्की को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के फैसले से पाकिस्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। यूएनओ का यह अभूतपूर्व कदम इस बात का सुबूत है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र है। आतंकवादी धरती के सबसे बड़े कसाई हैं। ...और इन कसाइयों को पनाह देना और इनके जरिये भारत में दहशत फैलाना पाकिस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है। दोस्त मुल्क चीन तक पाकिस्तान की आतंकपरस्त नीति से आजिज आ चुका है।

मक्की को अभी तक चीन ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बचाता आ रहा था। मगर इस बार चीन ने अपना रुख को बदला और इस अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी को बचाने के लिए वीटो नहीं लगाया। चीन इसके पहले ऐसा जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद और लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के मामले भी ऐसा करता रहा है। अजहर मसूद कंधार प्लेन हाईजैक मामले का प्रमुख मुजरिम और हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टर माइंड है। मक्की लश्कर का सरगना और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का संचालक है। भारत लगातार पाकिस्तान के इन कसाई आतंकवादियों की करतूतें वैश्विक मंच पर उठाते हुए यूएनओ के जरिए इनपर अंकुश लगाने का प्रयास करता रहा है। भारत के इस अभियान को पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन मिलता रहा है।

पाकिस्तान की लगातार विश्व मंच पर किरकिरी होती रही है। ब्रिटेन तो पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश की संज्ञा दे चुका है। बावजूद इसके इस्लामाबाद अपनी आतंकपरस्त नीति से पीछे नहीं हट रहा। तुर्रा यह देता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है और उसने 80 हजार नागरिक शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा झूठ नया नहीं है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन खुलेआम अपनी गतिविधियां चलाते हैं। हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। इन दिनों पाकिस्तान में लोकल चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में तहरीक ए लब्बैक अपने सिंबल पर उम्मीदवार खड़ा कर रहा है।

यह वही तहरीक-ए-लब्बैक है, जिसने फ्रांस के कथित रूप से मोहम्मद साहब के अपमान के विरोध में पूरे पाकिस्तान में दो साल पहले गदर मचाई थी। इस संगठन ने कुछ पुलिस अधिकारियों समेत दर्जनों लोगों की हत्या कर दी थी। कइयों को बंधक बना लिया था। इसके खौफ की वजह से फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। इमरान की सरकार ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही पाकिस्तान सरकार और तहरीक-ए-लब्बैक के बीच आर्मी की मध्यस्थता में एक गुप्त समझौता हुआ। इसके बाद लब्बैक के सभी आतंकियों को छोड़ दिया गया।सभी मुकदमे वापस ले लिए गए।

इसी तरह अफगानिस्तान मामले में अपनी नकली इमेज बनाने के लिए इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तालिबान ए पाकिस्तान नाम के आतंकवादी संगठन को न सिर्फ अपने यहां पनाह दिया, बल्कि उन्हें तमाम सहूलियतें प्रदान कीं ताकि भारत को तालिबान और अमेरिका के मध्य होने वाली समझौता वार्ता से अलग रखा जाए। खुद को तालिबान खान कहलाना पसंद करने वाले इमरान ने तालिबान ए पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौता भी किया। आज वही तालिबान ए पाकिस्तान इस्लामाबाद के लिए काल बना हुआ है। खैबर पक्खथुनवा में रोज ही तालिबान ए पाकिस्तान के आतंकवादी सेना और पुलिस पर कातिलाना हमला कर रहे हैं। इस आतंकवादी संगठन का इतना खौफ है कि शाम ढले अफगानिस्तान की सीमा के पास के पाकिस्तानी थाने में तैनात अधिकारी और पुलिस जवान थाने छोड़कर भाग जाते हैं। अब तो अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार भी पाकिस्तान को मिटा देने की धमकी देती है। काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास पर हाल ही में हमला भी हुआ था।

पाकिस्तान अब भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी आतंकवाद समर्थक नीतियों के कारण ही पूरी दुनिया उससे हाथ मिलाने से गुरेज कर रही है।अरब और चीन भी उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। उल्टे मक्की के मामले में पाकिस्तान ने यह बयान जारी किया है कि चीन ने उसे भरोसे में लेकर ही मक्की के लिए वीटो लगाने से अपने को दूर रखा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नियम 1267 के तहत इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ऐंड लेवांट (दायस) ऐंड अलकायदा से जुड़े प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल होने के कारण मक्की को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से पिछले साल ही मक्की पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में किया था लेकिन तब चीन ने वीटो लगाकर मक्की को बचा लिया था। इस बार यूएनओ की अलकायदा प्रतिबंध समिति में शामिल चीन समेत सभी 15 देशों ने एकमत से मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। चीन ने हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यह माना जा रहा है कि बिगड़ती अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान से मिल रही लगातार निराशा के कारण चीन की भारत के साथ टकराव की नीति में अब लचक आने लगी है। चीन के होने वाले नए विदेशमंत्री का हाल ही में दिया बयान इसका उदाहरण है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया है, जिससे लगे कि उसने कोई सबक लिया है। सिवाय विदेशमंत्री बिलावल भुट्टो के इस बयान के कि पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रति राष्ट्रीय संकल्प पर ठीक से विचार करना होगा। हैरत यह है कि पाकिस्तान की पुलिस, आर्मी और अदालतें आतंकवाद पर समान मानदंड नहीं रखते। ईश निंदा पर तो मौत की सजा का प्रावधान है पर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देने वाले हाफिज सईद और मक्की जैसे अतंरराष्ट्रीय आतंकवादियों का बाल बांका नहीं बिगड़ता। दिखावे के लिए को कभी हाउस अरेस्ट तो कभी दो-चार-छह महीने की मामूली सजा देकर रिहा कर दिया जाता है। मक्की को 2019 में गिरफ्तार किया गया तो उसे कुछ महीने के लिए घर में ही सभी सुख सुविधाओं के साथ नजरबंद रखा गया। 2020 में गिरफ्तार किया गया तो केवल छह माह जेल की सजा सुनाई गई। इस वक्त उस पर टेरर फाइनेंस के दो मामले चल रहे थे। मक्की आज भी प्रतिबंध के बावजूद लश्कर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में चला रहा है। लाख टके का बड़ा सवाल है कि दाने-दाने के लिए परेशान पाकिस्तान अब भी कोई सबक सीखेगा क्या।

हमारे पुरातन लोकतांत्रिक मूल्य और जी-20

शिवप्रकाश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जी-20 के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। जी-20 के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम कुछ निश्चित प्रतिनिधियों के कूटनीतिक कार्यक्रम न होकर भारत में समाज की सहभागिता से उत्सवों का रूप ले चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली की यह विशेषता है कि वह सरकारी योजनाओं को समाज के साथ जोड़कर संपूर्ण समाज का कार्यक्रम बनाते हैं। उनके द्वारा घोषित लक्ष्य 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' विश्व को जोड़ने का माध्यम बना है। यह भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का साकार रूप है। भारत जी-20 के माध्यम से विविधता युक्त भारत के लोकतान्त्रिक पद्धति से विकास के मॉडल (डेवलपमेंट,डायवर्सीटी, डिमोक्रेसी) को विश्व के सम्मुख रखना चाहता हैं।

इस वर्ष इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयों के मध्य बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अभी तक हम भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। जहां दुनिया के लोकतंत्र में संकट आए, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी लोकतंत्र सेना के बूटो तले रौंदा गया, वहीं हम सफल लोकतंत्र सिद्ध हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने को केवल बड़े लोकतंत्र न कहकर लोकतंत्र की जननी के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि भारत में वेदकाल से लोकतंत्र की परंपरा रही है।

गुलामी के कालखंड में हमारे 'स्व' को भुलाने का योजनाबद्ध प्रयास हुआ। हमको पढ़ाया एवं सिखाया गया कि भारत का अपना कुछ नहीं था, हमको सभी कुछ अंग्रेजों ने ही दिया है। गणित, ज्ञान-विज्ञान, कला, साहित्य, विकास अवधारणा आदि सभी अंग्रेजों से ही हमें विरासत में मिली है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि भारत में कोई शासन प्रणाली भी नहीं थी। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भी हमको अंग्रेजों की ही देन है। सुनियोजित मैकाले शिक्षा पद्धति से अध्ययन करने के बाद निकला भारत का भी एक बड़ा वर्ग इसी को सत्य मानने लगा।

हमको पढ़ाया गया कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र एथेंस गणराज्य है। एथेंस राज्य तानाशाही से मुक्त होकर प्रथम गणराज्य बना जिसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। एथेंस गणराज्य से हजारों वर्ष पूर्व भारत में वेदकाल से ही लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ था। ऋग्वेद में गणतंत्र शब्द का प्रयो 40 बार एवं अथर्ववेद में 9 बार प्रयोग हुआ है। राजा के द्वारा अपने सहयोगियों से परामर्श कर शासन चलाने के उदाहरण ऋग्वेद में विद्यमान हैं। राजा एवं उसके सहयोगियों से बनने वाले समूह को 'समिति' नाम से संबोधित किया गया। समिति की बैठकों में राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी जैसे कि 'राजा न सत्या: समितिरियान:' (जो राजा समिति की बैठक में नहीं आता वह सच्चा राजा नहीं है)

वेदों में तीन प्रकार की सभाओं का वर्णन है। जिसमें 1. विद्यार्यसभा (शिक्षा संबंधी) 2. धर्मार्य सभा (न्याय संबंधी) 3. राजार्य सभा (शासन प्रशासन से संबंधित) के माध्यम से शासन संचालन के प्रमाण मिलते हैं। समिति के समान ही सभा भी शासन संचालन का माध्यम थी। इसके अनेक प्रमाण साहित्य में उपलब्ध हैं। सभा की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा है कि वह सभा सभा नहीं जिसमें अच्छे लोग नहीं। अच्छे लोग वह हैं जो राग द्वेष छोड़कर न्याय की बात करते हैं। 'न सा सभा यत्थम न सन्ति संतो'।

महाभारत के शांति पर्व में जनसदन का उल्लेख है। शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को गणराज्य का महत्व समझाते हुए कहा 'जनता के साथ सीधे जुड़ाव का माध्यम गणतंत्र है'। बौद्ध काल में शाक्य, कोलिओ, लिच्छवि, वज्जी, पिप्पलवन, अलल्पवन सभी प्रजातांत्रिक गणराज्य के उदाहरण हैं।

संविधान सभा में बोलते हुए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2000 पूर्व उत्तर से दक्षिण गए हुए वणिको (व्यापारियों) के साथ राजा के संवाद का उल्लेख किया है। जब राजा पूछता है कि आप का राजा कौन है ? तब व्यापारी ने उत्तर दिया कि हममें से कुछ पर परिषद शासन करती है, कुछ पर राजा। पतंजलि, कौटिल्य आदि सभी भारतीय विद्वानों के साहित्यों मे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। विदेशी विद्वान मेगस्थनीज, ह्वेनसांग आदि ने भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में लिखा है। भारत में लोकतंत्र की सफलता का रहस्य यह है कि भारत के सामान्य समाज में स्वभावत: ही लोकतंत्र का भाव कूट-कूट कर भरा है। दुनिया के अनेक देशों में वहां के राजा की तानाशाही प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। वहीं भारत में सकारात्मक भाव से लोकतंत्र जन्मा है। भारतीय संस्कृति में मानव मन का जितना गहन अध्ययन हुआ है उतना अन्यत्र नहीं दिखता। भारत की समृद्ध परंपरा से उद्भूत अध्यात्म इसका कारण है। ऋग्वेद का मंत्र : संगच्छध्वं संवदध्वं। सं वो मनांसि जानताम्। समानो मन्त्र: समिति: समानी।

अर्थात: हम एक दिशा में चलें, एक समान बोलें, सभी के मनोभाव को जानें, हमारी समिति समान हो, सभी का मंत्र (लक्ष्य) एक हो।

भारत में यह लोकतंत्र का सकारात्मक भाव प्राचीन काल से उत्पन्न हुआ। जो भारतीय जन-मन के संस्कारों में स्थित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय सभी को समान मताधिकार देकर इसी भाव को पुष्ट किया था। प्रधानमंत्री भारत को लोकतंत्रकी जननी कहकर इसी ऐतिहासिक सत्य को विश्व के सम्मुख उद्घाटित कर रहे हैं। जी-20 इसी प्रकार के भारतीय वैशिष्ट्य को स्थापित करने का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के पंच प्रण को साकार कर भारत को मानसिक गुलामी से भी मुक्ति प्रदान करेगा।

(लेखक - भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है)

आजकल

बनी रहे पद की मर्यादा

इस अधिकार के साथ इसकी गरिमा का खयाल रखने की जिम्मेदारी भी लोगों की ही है। अगर इस सुविधा को बेलगाम बोली और बर्ताव की छूट के तौर पर देखा जाएगा तो इस पर सवाल उठेंगे। खासतौर पर किसी जिम्मेदार पद पर बैठ कर कोई जनप्रतिनिधि इस संवैधानिक अधिकार की गरिमा कायम रखने के बजाय बोली में मर्यादा का खयाल रखना जरूरी न समझे, तो यह एक चिंताजनक स्थिति है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल के पास यहां के शासन को संचालित करने के लिए पद से जुड़े कई अधिकार हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि और विशेष रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते अपने पद और उसकी मर्यादा को बनाए रखना भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके उलट हालत यह है कि अगर उनकी सरकार में कामकाज से जुड़ी प्रक्रिया से संबंधित कोई अड़चन खड़ी होती है तो इस पर विचार करने के बजाय वे नाहक बिफर जाते हैं। जबकि उनके पद और कद को देखते हुए यह स्थिति खुद उनकी ही गरिमा को कठघरे में खड़ा करती है!

गौरतलब है कि सरकारी कामकाज में उपराज्यपाल की ओर से कथित हस्तक्षेप के आरोप के साथ अरविंद केजरीवाल न सिर्फ उनके कार्यालय तक निकाले गए जुलूस में खुद शामिल हुए, बल्कि इससे बाद उन्होंने कुछ ऐसी भाषा में बात की, जिसे मर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने उपराज्यपाल पर 'सामंती मानसिकता से ग्रस्त' होने का आरोप तो लगाया, लेकिन खुद ही जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह उनकी मंशा को कठघरे में खड़ा करता है।

खबरों के मुताबिक, कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने के फैसले से उपराज्यपाल की असहमति के बाद विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि 'कौन हैं एलजीज कहां से आए वे हमारे सिर पर सवार हैंज बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह!' सवाल है कि वे जिस पद पर हैं और उससे जिस तरह की जवाबदेही जुड़ी है, क्या ऐसी भाषा में बात करना उनके लिए उचित है? अगर सरकारी कामकाज में उपराज्यपाल की आपत्ति में नियम-कायदे से संबंधित कोई गड़बड़ी है, तो इसके समाधान के लिए शासन के ढांचे में कोई प्रक्रिया निर्धारित होगी। मगर इसके तहत मुख्यमंत्री पद की मर्यादा का निर्वाह करने के बजाय वे अशिष्ट लहजे में अपनी असहमति दर्ज करते हैं, तो इसे कैसे देखा जाएगा? सही है कि दिल्ली के मतदाताओं ने उन्हें चुन कर भेजा है।

पहले बुनियादी ढांचा बनाने की जरूरत

मुद्दा

- ऋषभ मिश्रा

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए कंपनियों द्वारा लगाये गए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का देशभर में 5 से 25 फ़ीसदी तक ही इस्तेमाल हो पा रहा है। दरअसल, देश में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक तौर पर नहीं अपनाया गया है। इसका एक मुख्य कारण इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क़ीमत पेट्रोल या डीज़ल गाड़ियों की तुलना में ज़्यादा होना है। हालांकि सरकार कई तरह की रियायतें दे रही है लेकिन फिर भी पेट्रोल-डीज़ल की गाड़ियों के मुकाबले ई-वाहनों की कीमत ज़्यादा ही है।

दरअसल, ज्यादातर ई-वाहन दोपहिया (9 लाख से ज्यादा पंजीकृत दोपहिया) हैं इनमें से करीब 80 फ़ीसदी वाहन घरों पर ही चार्ज किये जाते हैं लेकिन इसमें लंबा वक़्त लगता है। जैसे सुबह गाड़ी तैयार रखने के लिए उसे रात में चार्ज पर लगा दिया जाता है। 'ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिसिएंसी' के मुताबिक दोपहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज 84 किलोमीटर प्रति चार्ज बताई गई है। वहीं चौपहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की औसत रेंज 150-200 किलोमीटर प्रति चार्ज बताई गई है।

भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन की भारी कमी है। जिस तरह हमें हर हाइवे या सड़क पर पेट्रोल पंप दिख जाते हैं उसके मुकाबले चार्जिंग स्टेशन बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं। भारत में कुल कारों में से इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी महज 1 फ़ीसदी है। इसके लिए बड़ी संख्या में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत है क्योंकि कारों को लम्बी दूरी तक चलना होता है। मगर अभी गिनी चुनी इलेक्ट्रिक कारें ही सड़कों पर नज़र आती हैं।

इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लीथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल है। ये बैटरियां 6 से 7 साल तक ही चल पाती हैं इसके बाद इन्हें बदलना पड़ता है। बैटरियों की कम लाइफ़ इसे खरीदने वालों के मन में संशय पैदा करती है। दरअसल एक बैटरी की कीमत किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के तीन-चौथाई रकम के बराबर होती है। हालांकि सरकार ने पिछले साल 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (पीएलआई) योजना को मंज़ूरी दी थी। यह योजना देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के निर्माण के लिए लाई गई है जिससे बैटरी की कीमतों को कम किया जा सके।

भारत में बिज़नेस कंसल्टिंग फर्म 'बेन एंड कंपनी' के अनुसार देश में अभी करीब 5000 सार्वजनिक और निजी चार्जिंग स्टेशन हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या काफी कम होने की वजह से चार्जिंग स्टेशनों के लिए कारगर आर्थिक मॉडल अभी सामने नहीं आ पाया है। कई बार यह सुझाव दिया जाता है कि पेट्रोल पंप पर ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा दी जानी चाहिए लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने में 1-5 घंटे का समय लगता है ऐसे में ईवी को चार्ज करना किसी गाड़ी में पेट्रोल, डीज़ल या सीएनजी डलवाने जितना तेज़ी से नहीं हो सकता। साथ ही चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ी को कुछ घंटों के लिए छोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा सकती है। 'बैटरी स्वैप' करने की सुविधा एक बेहतर विकल्प हो सकती है, जिसमें खाली बैटरी को उतनी वारंटी वाली फुल बैटरी से तुरंत बदल दिया जाए। दिल्ली-एनसीआर तथा उत्तर भारत के अन्य शहरों में इसके सार्वजनिक फ़ास्ट चार्जर का उपयोग काफी कम किया जा रहा है। दरअसल चार्जरों का औसत इस्तेमाल करीब 15 फ़ीसदी ही हो पा रहा है। शहर के अंदर यह 15 फ़ीसदी से भी कम है, लेकिन राजमार्गों पर विकल्प सीमित रहने से इनका 25 फीसद तक इस्तेमाल हो रहा है। चार्जिंग स्टेशन की कमी के साथ ही गाड़ियों की रेंज को लेकर भी ड्राइवरों के मन में डर बना रहता है। अक़्सर लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कम रेंज से परेशान होते हैं। बैटरी और चार्जर बनाने वाली 'एक्सपोनेंट एनर्जी' हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 मिनट में चार्ज करने वाले चार्जर पर ज़ोर दे रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए ज्यादा पावर की ज़रूरत होती है। साथ ही कम समय में चार्ज करने वाले चार्जर से अधिक वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। कुल वाहनों में वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 10 फ़ीसदी है लेकिन कुल ईंधन खपत का 70 फ़ीसदी तक पारम्परिक वाहनों में जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रति एक चार्जिंग स्टेशन पर रोजाना औसतन 9 वाहन आते हैं। बाजार में ई- वाहनों की संख्या बढ़ने पर 'हाइपर चार्जर' का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ेगा।